शोध मंथन Vol. XVI No.I Jan.- Mar. 2025 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

ट्रंप 2.0: भारत के लिए अवसर और चुनौतियां

प्राप्तिः 10.03.2025
स्वीकृतः 18.03.2025

डॉ0 कुमारी अनुपमा
असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान विभाग)
श्रीमती बी.डी. जैन गर्ल्स (पी. जी.) कॉलेज
आगरा छावनी, आगरा
ईमेलः anupamasurendra42@gmail.com

3

सारांश

एक तरफ बदलते हुए वर्तमान वैश्विक अनिश्चितता और दूसरी तरफ अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्व में ट्रंप सरकार का आना एक बार फिर से वैश्विक परिदृश्य में हलचल के वातावरण को जन्म देता प्रतीत हो रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा अमेरिका का स्वर्णिम युग अभी शुरू हो रहा है, साथ ही वो 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति की घोषणा कर चुके हैं। अमेरिका की घरेलू नीतियों से लेकर विदेशनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे व्यापार नीतियों, आव्रजन नीतियों, जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने से लेकर रसिया–यूक्रेन संघर्ष, इजराइल–गाजा संकट, चीन के साथ ट्रेड वार तथा हिंद–प्रशांत क्षेत्र में चीन की उपस्थिति को कम करने के लिए क्वाड जैसे मंच पर भारत के साथ खड़ा होना जैसे मुद्दों ने भारत को अपने विदेशनीति पर विचार करने के लिए बाध्य कर दिया है। ताकि भारत, अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक साझेदारी को बरकरार रखते हुए अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ भी अपने संबंधों को संतुलित कर सके।

मुख्य बिन्दु

भारत, अमेरिका, चीन, हिंद–प्रशांत क्षेत्र, ट्रेडवार, वैश्विक संतुलन

प्रस्तावना

बदलते हुए वर्तमान वैश्विक अस्थिरता की दशा में तथा वर्ष 2025 के शुरुआत में अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन के बाद वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक भारत–अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों की बात है स्वतंत्रता के बाद से दोनों देशों के पास लोकतंत्र, उदारवाद, और बहुलवाद जैसे साझा मूल्य थे लेकिन बावजूद इसके सन् 1991 तक दोनों के संबंध सामरिक दृष्टि से तनाव पूर्ण रहे। शीतयुद्ध का अंत दोनों देशों के बीच नए अध्याय की शुरुआत थी। यह बदलाव कई राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक कारकों के कारण हुआ था। प्रधानमंत्री बाजपेयी ने साझा मूल्यों और भू–राजनीतिक हितों पर जोर देते हुए दोनों देशों को ''स्वभाविक सहयोगी'' कहा। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ओबामाः ने साझेदारी को ''21वीं सदी का निर्णायक रिश्ता'' बताया।[1]

आगे वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा–आपसी साझेदारी ने दीर्घकालीन गठबंधन बनाने के लिए ऐतिहासिक हिचकिचाहट को दूर कर लिया है।[2]

पिछले कुछ दशकों में भारत–अमेरिका रणनीतिक और आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और प्रमुख रक्षा सहयोगी है। ये उपलब्धियाँ संबंधों में लगातार मजबूती को रेखांकित करती है। जिसमें दोनों देश व्यापार, प्रौद्योगिकी रक्षा और ग्लोबल गवर्नेंश पर सहयोग कर रहे हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल (2017–2021) के दौरान भी भारत और अमेरिका संबंधों को एक मजबूत नींव मिली। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग तथा सन्धियों के माध्यम से अपने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया।

1. भू–राजनीतिक सहयोग के तहत दोनों देशों ने जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 'क्वाड' को पुनर्जीवित किया।
2. यू.एस. पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर यू.एस. इंडो–पैसिफिक कमांड कर दिया जो भारत की रणनीतिक भूमिका को दर्शाता है।
3. व्यक्तिगत कूटनीति के तहत ''हाउडी मोदी'' और ''नमस्ते ट्रम्प'' जैसे आयोजनों को उजागर किया, जिसमें दोनों देशों के नेताओं ने घनिष्ठ संबंध तथा आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया।
4. रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में भारत को प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में नामित किया गया।
5. भारत और अमेरिका के बीच मजबूत आर्थिक संबंध दोनों देशों के बीच एक मजबूत आधारशिला बने हुए है। अमेरिका वस्तुओं और सेवाओं के लिए भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।
6. अमेरिका भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का प्रमुख स्त्रोत रहा है। वर्ष 2023 में अमेरिका का भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49.56 बिलियन यू.एस. डॉलर रहा।

हाल ही में अमेरिका में राजनीतिक नेतृत्व के बदलाव तथा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणाओं ने भारत के लिए अवसर के साथ ही चुनौतियों को भी प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनकी प्रमुख घोषणाएँ घरेलू और विदेशनीति दोनों ही स्तरों पर प्रमुख परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। शपथ ग्रहण के दौरान ट्रंप ने कहा हमारी नीति 'अमेरिका फर्स्ट' की होगी। जिसके अन्तर्गत उन्होंने भ्रष्टाचार और महँगाई खत्म करने का वादा किया। इसके अलावा अवैध प्रवासियों पर भी उन्होंने बयान देते हुए कहा–''हम उन्हें वहीं छोड़कर आयेंगे जहाँ से वे आए थे।''[3]

वास्तव में अमेरिका की विस्तृत रणनीति हमेशा ही आर्थिक, कूटनीतिक, सामरिक, सैन्य और सूचना की ताकत इस्तेमाल करके अपने घरेलू हित साधने और वैश्विक व्यवस्था की रूप रेखा को अपने अनुसार आकार देने का प्रयास रहता है।[4]

ट्रंप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अमेरिका की आर्थिक मदद से पूरी दुनिया को फायदा हुआ है और वक्त आ गया है कि अमेरिका को इस पर रोक लगाने की जरूरत है। ट्रंप सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विकास में सहायता देने वाली अमेरिकी एजेंसी USAID के पुनः मूल्यांकन की शुरुआत की है।

अंतर्राष्ट्रीय सहायता के मामले में अमेरिका की नई सरकार की नीति निरपेक्षता, निष्पक्षता और मानवता पर आधारित सिद्धातों के अनुरूप नहीं होगी बल्कि ट्रंप सरकार की नीति व्यवहारिकता पर आधारित होगी।[5] इस प्रकार ट्रंप सरकार के आने से अमेरिकी नीतियों में बड़े–बड़े परिवर्तन होने की पूरी संभावना है। तथा भारत जिन विकल्पों के तहत अमेरिका के साथ जुड़ा है उसकी जड़ मे व्यापार और अप्रवासी मुद्दे के साथ–साथ सामरिक और सैन्य कारण भी हैं।[6]

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग के लिए रंखांकित क्षेत्र

रणनीतिक सहयोगः– अमेरिका इण्डो–पैसिफिक क्षेत्र में उपस्थिति बनाये रखने तथा चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने को इच्छूक है वहीं दूसरी तरफ भारत भी इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड जैसे मंच पर अमेरिका के साथ मजबूती से खड़ा होने को तैयार है। ट्रंप की प्राथमिकताओं में अभी भी भारत–अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का महत्व बकरार है। दोनों देश साथ मिलकर उभरती हुई प्रौद्योगिकियों जैसे स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमता और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम द्वारा अपने नवाचारतंत्र को मजबूत कर सकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण और स्वास्थ्य सुरक्षा में सहयोग से द्विपक्षीय संबंधों के नये रास्ते खुलेंगे।

लेकिन ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों ने अनेक तरह की चुनौतियाँ पेश करती हुई प्रतित हो रही है। अमेरिका ने भारत के संबंध में भी ''रेसिप्रोकल टैंरिफ'' लागू करने की घोषणा कर दी है। इस नीति के तहत भारत जितना शुल्क अमेरिकी उत्पादों पर लगाएगा, अमेरिका भी भारतीय वस्तुओं पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। इस प्रकार अमेरिका में बिकने वाले भारतीय समान महंगे हो सकते हैं, जिससे निर्यात प्रभावित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत यदि टैरिफ कम करता है तो अमेरिकी समान सस्ता हो सकता है, लेकिन शुल्क बढ़ाने पर महंगा भी हो सकता है। अमेरिका का ऐसा मानना है कि व्यापार संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों देशों को समान शुल्क नीति अपनानी चाहिए।[7]

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2024 में दोनों देशों का व्यापार करीब 130 अरब डॉलर था। दोनों देश 2030 तक इसे 500 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते है। दोनों देशों के कारोबारियों ने यहाँ भारी निवेश कर रखा है।

ट्रंप सरकार के द्वारा आव्रजन नीतियों में परिवर्तन जैसे प्रतिबंधात्मक वीजा व्यवस्था, विशेष रूप से एच–1 बी धारकों के लिए भारत के आई.टी. क्षेत्र और अमेरिका में कार्यरत कुशल पेशेवरों को भी प्रभावित कर सकती है। बड़ी संख्या में भारतीय नौकरी के लिए अमेरिका जाते हैं, लेकिन अनेक ऐसे भी है जो यहाँ अवैध तरीके से जाते हैं। ट्रंप अवैध रूप से पहुँचे भारतीयों को निकालने में लगे हुए हैं। लेकिन जिस अपमान जनक तरीके से हथकड़ी और बेड़ियाँ लगाकर भेज रहे है उससे वो भारत को यही संदेश देना चाहते हैं कि उसे आर्थिक–व्यापारिक मामले में अमेरिका के समक्ष झुकना ही पड़ेगा।[8]

नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक, ''ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन'' के भूराजनीतिक विश्लेषक हर्ष पंत ने कहा– ''ट्रंप प्रशासन के साथ समस्या यह है कि टैरिफ सहित कई मुद्दे सामने है।'' तो आप कहाँ झुकेंगे ओर कहाँ बात करेंगे।

लेकिन वर्तमान वैश्विक अस्थिरता की दशा जैसे यूक्रेन–रूस संघर्ष, इजरायल–गाजा संकट, पश्चिम एशिया में अस्थिरता, चीन की अक्रामकता जो लगातार वैश्विक और क्षेत्रीय शांति के लिए

चुनौती बनी हुई है। दक्षिण और पूर्वी चीन सागर मे उसकी सैन्य कार्रवाइयां, ताइवान पर आक्रमणकारी नीति और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी रणनीतियाँ चिंता का विषय है। इसके साथ ही पड़ोस में उभरते हुए घटनाक्रम जैसे पाकिस्तान–अफगानिस्तान में बढ़ता तनाव, म्यांनमार और बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता। अतः इन सभी वैश्विक असुरक्षा एवं अनिश्चितता की स्थिति में भारत को मजबूत कूटनीतिक, सुदृढ़ सैन्य नीति अपनाने की आवश्यकता है। भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्रता के द्वारा स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए अमेरिका के साथ अपनी बढ़ती साझेदारी को संतुलित करना होगा तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी विशेष रूप से रूस और अन्य वैश्विक शक्ति के साथ अपने संबंध संतुलित रखना होगा।

संदर्भ

1. संकलप्त, 2025 abpline.com/news
2. श्रीवास्तवा, स्वराज 2025, ''ट्रंप के रेसीप्रोकल टैरिफ पलान से भारत पर पड़ेगा कितना असर, क्या है यू एस ट्रेड पॉलिसी में बदलाव का मतलब'' दैनिक जागरण (समाचार पत्र)
3. कुमार, सौरभ 2025 abpline.com
4. संपादकीयः भारत अमेरिका संबंधों को नया आयाम, 15 फरवरी 2025 ''नवप्रदेश डेस्क''।
5. मिश्रा, विवेक (2024), 'ट्रंप 2.0ः उम्मीदों का सवेरा या कयामत के आसार' by ORF (Observe Research Foundation) , Raisina Debates.
6. जोशी, मनोज (2024), ''बाइडन युग में कैसा रहा भारत–अमेरिका संबंध'' by Observe Research Foundation, (ORF), Raisina Debate.
7. सांवरिया, नरेंद्र (2024), ''भारत–अमेरिका के रिश्तों की लिखी जायेगी नई इबारत'', दैनिक जागरण (समाचार पत्र)।
8. ''अमेरिका में फिर आया ट्रंप युग, अपने पहले संबोधन में बोले, राष्ट्रपति ट्रंप–मेरी नीति 'अमेरिका फर्स्ट' की होगी'' by ddnews.gov.in.